[Dr. Subramanian Swamy]

I think, what is more important is clarity in our mission as to what we consider Chinese reciprocity. What do we want the Chinese to do and what are the channels that we are opening for, to convince that we are at one with them? After all, they have taken a miss to our policy towards Kampuchea and we have been isolated on the issue of Kampuchea. (*Interuptions*).

PROF. MADHU DANDAVATE: Get it set right.... (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes, certainly. There is a way of getting that back. There is a way of doing that in international diplomacy. There is no doubt about it. We must get back every inch of our territory. In the Janata Government, Shri Morarji Desai had made it clear that India's relations can never be normal with China unless they return the territory which belongs to us. But the question is how to get it. It is here that diplomacy is necessary and it is here that the Government has to show statesmanship.

The last one year has been a dismal record of failures and a record of missed opportunities. I hope the Minister will come and offer some hope for the next year.

With these words, I thank you very much.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINETEENTH REPORT

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move:

"That this House do agree with the Nineteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th March, 1981"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Nineteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th March, 1981."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION *RE*. FORMATION OF A NATIONAL YOUTH COMMISSION TO SOLVE UNEMPLOYMENT PROBLEM OF EDUCATED YOUTH—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further discussion on the following Resolution moved by Shri Phool Chand Verma on 13 March, 1981:—

"In view of the fact that the present educational system does not equip and prepare the youth for meeting the challenges of life, the whole planning process has failed to channelise our youth power into productive channels and there is lack of direction in providing employment to the educated youth during the Sixth Plan period; this House urges upon the Government to constitute a National Youth Commission immediately to examine and suggest, within a period of six months, appropriate measures for solving the problem of unemployment amongst the educated youth.'

Time allotted was two hours. Time already taken is 1.42 hours. Shri Nawal Kishore Sharma was on his legs. After he completes his speech, the Minister will reply.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): उपाध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव के संबंध में यह कह रहा था कि बेकारी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में कई मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस देश के अन्दर डिगनीटी आफ लेबर नाम की कोई चीज नहीं है। इसलीए हमारे देश का

पढ़ा-लिखा नौजवान, चाहे वह डाक्टर हो, चाहे वह इन्जीनियर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर-ग्रेजुएट हो, चाहे कोई फार्मिस्ट हो--उन सब के मन में एक ही तमन्ना रहती है कि वह किस तरह से व्हाइट-कालर्ड जाब हासिल कर सकें और इस प्रकार पढ़े-लिखे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश में आजादी के आने के बाद शिक्षा में जो विस्तार हुआ, कालेजेज खुले, युनिवर्सिटीज खुलीं, स्कूल्स और हाई-स्कूल्स खुले, जो कि स्थिति को देखते हुए आवश्यक थे। उस विस्तार के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार लोगों को एम्प्लाय-मेंट आपर्चुनीटीज तो क्रीएट कर सकती है, उसके लिए प्रयत्न भी किए जा सकते हैं, लेकिन सब लोगों को व्हाइट-कलर्ड जाब दे सकना संभव नहीं है--इस लिए यह समस्या गम्भीर बनती चली जा रही है। इस समस्या के गम्भीर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज युवकों में भयंकर फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ला-एंड-आर्डर की कोई प्राब्लम्स उनके द्वारा क्रिएट की जाती है। आंकड़ों से पता लगता है कि बहुत से बैंक डकैतियां बहुत सी रेलों की लूटपाट और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुत से लोग जो नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ एट्रैक्ट होते हैं, उसके मूल में जो एक फ्रस्ट्रेशन है, यही उसका एक कारण है। बेरोजगारी के कारण भी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका यह भी एक कारण है।

उपाध्यक्ष जी, असल में दुर्भाग्य से इस देश में मेरी पार्टी की सरकार है, उसकी इस असफलता को मैं मंजूर करूंगा। बरा-बर यह कहा जाता रहा है कि शिक्षा की पद्धति में शिक्षा की रीति-नीति में परि-वर्तन होना चाहिए--राष्ट्रपति से लेकर प्रधान मंत्री से लेकर यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमी-शन के चेयरमैन से लेकर शिक्षा मंत्री बार-बार यही कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषरहित नहीं है, दोषपूर्ण है। मैकाले ने जो क्लर्क पैदा करने के लिए, गुलाम पैदा करने के लिए शिक्षा प्रणाली चालू की थी, यह देश उसी प्रणाली को आज भी अपने सिर पर ओढ़े हुए है। परिवर्तन की सब ने बात की।

अनेक कमीशन बने, अनेक कमैटियां बनी, चूंकि आप ने समय के बारे में मुझे वार्निंग दे दी है, इस लिए मैं उन के आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं--इन सब की रिपोर्ट्स आईं, रिकमैण्डेशन्ज आईं, लेकिन शायद पार्लिया-मेंट की लाइब्रेरी में या शिक्षा मंत्रालय के किसी उच्च अधिकारी के पास धूल चाट रही है। मैं मानता हूं--यह एक मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है जब हम को शिक्षा नीति में परिवर्तन के लिये कुछ बोल्ड-स्टेप्स उठाने पड़ेंगे . . .

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : सजेशन दीजिये।

श्री नवल किशोर शर्मा : सजेश्चन देता हूं, आप जाइये मत। हम को फैसला करना होगा कि शिक्षा को सिलैक्टिव बनायें। आज यूनीवर्सिटीज में ढोर-डंगर की तरह से जानवरों की तरह से, एक-एक क्लास में 80 से 100 लड़के तक पढ़ते हैं, चाहे उन का एप्टीचूड उस सब्जैक्ट में हो या न हो। इस के अतिरिक्त आज यूनीवर्सिटीज में जो प्रथा चल रही है--मैं मानता हूं--कि विद्यार्थियों को आर्गेनाइज होने का हक है, यूनियन बनाने का भी हक है, लेकिन जिन की पढ़ने में रूचि नहीं है, यूनीवर्सिटी में सिर्फ इस लिये जाते हैं कि रोजगार तो मिलता नहीं है, घर वालों से पैसे लेने का यह साधन बन जाता है कि क्लास में भरती हो जाओ, उसके बाद लीडर बनकर सिनेमा के पास के लिये हड़ताल करो, परीक्षा में नकल करने की इजाजत के लिये परीक्षा का बायकाट करो और कभी-कभी तो बड़ी अजीब-अजीब मांगे लेकर हड़ताल और प्रदर्शन किये जाते हैं। राजनीतिक दल, खास तौर से विरोधी दल और कभी-कभी मेरे लोग भी उस में शरीक होते हैं, उनको अपना इंस्ट्रू-मेन्ट बनाते हैं . . . .

श्री फूल चन्द वर्मा: कभी-कभी क्यों ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सही है, इस लिए कि हम डिसिप्लण्ड लोग हैं।

श्री फूल चन्द वर्मा: जब विरोध में थे तब बार-बार करते थे, आज कभी--कभी करते हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा: मैंने कहा है कि हम डिस्प्लेण्ड लोग हैं।

हम को इस के बारे में सोचना पड़ेगा कि आज जो टीचर और टाट के बीच में कम्यूनिकेशन-गैप हो गया है, टीचर नहीं जानता कि मेरा टाट कौन है और टाट को पता नहीं कि मेरा टीचर कौन है यह जो स्थिति पैदा हो गई है, मकेनाइज्ड तरीके से मास्टर, अध्यापक या प्रध्यापक पोन घन्टे या एक घन्टे के लिये समय निकाल कर क्लास में जाता है और राम-राम कर के वापस आ जाता है, कहता है--खुदा का शुक्र है, आज की तनख्वाह तो पक गई--इस शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। इस लिये मेरी यह मांग है कि यूनीवर्सिटीज में एडमीशन सिलेक्टिव होना चाहिये। किसी भी क्लास में एक निश्चित तादाद से ज्यादा स्टूडेन्टस नहीं लिये जाने चाहियें। यूनीवर्सिटीज और कालिजज को प्रेशर टैकिटक्स--जिस के लिये पोलिटीशियन्ज जिम्मेदार हैं--मुक्त रखना चाहिये। मेरा तो सुझाव है कि जिस तरह से मैडिकल में एडमीशन के लिये पहले पी. एम. टी. का इम्तिहान होता है, उसी तरह से छात्रों की कैपेबिलिटी और एप्टीच्यूड का इम्तिहान होना चाहिये, जो उस में पास हों, उन के मैरिट के आधार पर जितनी सीटें हों उन के मुताबिक एडमीशन दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय आय का दुरूपयोग है जो इस तरह से छात्रों को भरती कर लिया जाता है। देश के गार्डियन्ज पर यह एक बोझा है। आज की शिक्षा पद्धति में जो इम्तिहानों का तरीका है उस में आधारभूत परिवर्तन की जरूरत है। कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने भी इस के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री जी उस चिन्ता को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधान मंत्री जी का काम तो चिन्ता व्यक्त करना ही हो सकता है। उसके अनुरूप नीति-निर्धारित करने का काम शिक्षा-मंत्रालय का है। मुझे खेद है इस बात का कि आज की इस डिबेट का, जिसका सीधा संबंध शिक्षा-मंत्रालय से है, लेकिन शिक्षा-मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि इस डिबेट में भाग नहीं ले रहा है। श्रम-मंत्रालय रोजगार नहीं दे सकता। इसका सीधा संबंध शिक्षा-मंत्रालय से है और जब तक शिक्षा-मंत्रालय का प्रतिनिधि इस डिबेट में उपस्थित नहीं होता है और इस डिबेट में भाग नहीं लेता है तब तक यह डिबेट बेमानी है।

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, please send the Marshal and call the Education Minister.

SHRI PHOOL CHAND VERMA: Yes, I support.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister of State is here.

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि मार्शल को भेजिए और शिक्षा मंत्री को बुलाइए, ये स्कूलों में भी मार्शलों को बुलाकर मास्टरों की दुर्गति करवाते हैं, यही सिखाते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि समस्या के समाधान के लिए समय रहते कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए।

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या कदम उठाने चाहिए?

श्री नवल किशोर शर्मा: मैंने बता दिया है, समझ में आना चाहिए, उसके लिए दिमाग का दायरा थोड़ा सा खोलना पड़ता है। आप चड्डी वाली पार्टी के दायरे में बंधे हुए हैं, वह आपके दिमाग को नहीं खोल सकती। मुझे अफसोस है, माफ करना मैं अपने शब्दों पर आफसोस जाहिर करता हूं।

श्री फूल चन्द वर्मा : चड्डी कहां दिख रही है?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will also have a chance to reply. Do not exhaust everything now. &

श्री नवल किशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं वर्मा जी के इस प्रस्ताव की मूल भावना से सहमत

हूं, मगर प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इसमें आपरेटिव पार्ट में कमीशन की बात कही गई है। कमीशन तो बहुत बन गए, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए एक नया कमीशन बनाकर इस बेरोजगारी की समस्या को जो टालने वाली नीति रही है, उसमें एक कदम और बढ़ाना चाहते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Originally, two hours were allotted for this and there are still 8 more speakers.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): So, I request that time may be extended by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time of the Resolution by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): If the House so desires, I have no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House is unanimous in this.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Sir, injustice has been done to me. If I know that time would be extended, I could have spoken for some time more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You had already taken 5 minutes last time.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Sir, I rise to support this Resolution.

Sir, I give my full support to the prelude of this Resolution. But I have many doubts about the operative part of this Resolution and I agree with my friend who spoke before me that by merely appointing commissions this problem is not likely to be solved. The reason why I say so is that previous to this many commissions and many committees were appointed and these commissions and committees have made valuable suggestions and I would like to invite the attention of the Government and hon. Minister through you, Sir, to tell this August House as to whether the suggestions made by the various committees and commissions have been implemented. In my opinion many good suggestions have been made and I would like to high light some of those suggestions and I believe that if these suggestions are implemented, the problem can be solved to a certain extent.

Sir, I find from these notes with me that one Committee was appointed by the Forum of Education, New Delhi and its name is "Committee on Education" and this Committee had made certain recommendations. If this report is studied in depth and if the efforts are made to implement the suggestions as already alluded to, no doubt, we can help to solve the problem of unemployment of educated people. Before going to those suggestions it would be necessary to make only a mention of some figures in order to appreciate the suggestions made by this particular Committee.

As on 30th June 1980 we find that the total number of educated unemployed is 76,62,000 out of which 42,22,000 are matriculates, 19,82,000 are intermediate people, about 13,43,000 are graduates and 1,14,000 are post-graduates. It is in this background that some suggestions were made.

One more statistical data we have to take into consideration. That is the growth of percentage of educated job seekers. From 1961 to 1972 the growth in job seekers as far as matriculates are concerned is 12.8 per cent, Higher Secondary is 26.4 per cent, graduates and post graduates are 24.2 per cent. This is upto 1972. A good number is added from 1972 to March, 1980. In what way we can help these people and also the numbers which are going to be added in years

[Shri Bapusaheb Parulekar]

to come? It is suggested by a particular Committee that this particular problem can be solved by four ways. The first is by taking some steps to tone up administration. This item was named administrative remedies. The second is the social remedies. The third is educational remedies which have been specially referred to in the second part of the Resolution and the fourth is mobilisation of resources. It is not possible for me to go into all these four aspects. But I would like to mention a few of them. As far as the administrative remedies are concerned, I am going to make a request to the Government to consider the possibility of the suggestion which would give employment to thousands of educated people every year without spending any amount from the Government treasury. On the other hand if this suggestion is implemented, the jobs will be given to educated unemployed and Government money will be saved. In this connection the suggestion that has been made by this particular Committee is that the retirement age of the Government servants be reduced from 58 to 55. In doing so, we find that we will be in a position to provide jobs in Government service to the extent of one lakh or more. In five years we would be giving jobs to five lakhs of people. Leaving aside the matriculates, it will be possible for us to give relief to persons who are graduates and intermediates. In this connection, as I submitted earlier, it will be necessary to consider the data which I gave about the educated unemployed. I find that in the year 1971 there was collection of data from all Government offices as to how many persons usually retire at the age of 55 and the figures that were available then were somewhere between 65,000 to 70,000. It was in the year 1971. If we take into consideration the present position, we find that this number has gone to about a lakh. If the persons are made to retire at the age of 55, within this period 55-58, we would be in a position to give employment to a lakh of people every year.

I would like to highlight some of their observations and I quote from this particular report:

> "The retirement age of Govt. employees be reduced from 58 to 55 years........This would also cause no loss to the Government in financial terms as the persons to be retired would be drawing maximum in higher salary grades whereas fresh entrants will be recruited at the minimum start in the lowest pay grades. This will remove a lot of fossils in the Government and by bringing chain promotions in the lower and middle ranges work as a stimulant to efficiency."

They have even replied to the objections as to what will happen to persons of merit and all that. All those details have been given. It is not possible for me to go into all these details.

The second suggestion which they have made with reference to statistical data is the abolition of payment of overtime. They have worked on this aspect of the matter. After working it out, they have said that if this is done, this financial drain should be appropriately diverted to the creation of more job opportunities for the educated. It has been given in detail, giving statistics in this particular report. They have also mentioned that because of the procedure of paying overtime allowance, many of the employees do not work from 10 A.M. to 5 P.M. They start working only after 5 P.M. in order to get overtime allowance. I do not know whether this is true or not. I am only referring to this particular suggestion and the data collected and given in this particular report. You have to take into consideration whether this suggestion, if tried to be implemented, it would be possible for us to give jobs to other people. They say that the jobs to thousands of people, every year, could be given.

The third suggestion, as far as the administrative remedy is concerned, which they have made should be seriously considered. I quote:

"It is suggested that employment exchanges be set up for service in foreign countries by our nationals. It should be made binding on our nationals to accept foreign assignments through these employment exchanges and not direct and also to execute a bond to return after a specified period or earlier, if needed in the national interests. The placement service in foreign countries may also be taxed suitably depending upon the range of income, cost of living etc. This scheme is thus likely to be self-financing and may also provide a check on the prevailing brain-drain."

If worked properly, it will solve the problem of educated unemployed. Here also, they have given statistics. They have worked on this particular project.

What I am requesting the Government is, instead of going in for a new commission, they should take into consideration the various suggestions made by the committees which were appointed earlier. I would like to ask the hon. Minister as to whether they have given any thought to these particular suggestions and whether they have tried to implement any of these suggestions and, if so, what is the result and, if not, whether the Government will consider implementing these particular suggestions and, if not, why not. This is with reference to administrative remedy.

With reference to social remedy, I would only mention two of them. This particular committee has mentioned that these suggestions would be helpful in solving the problem of educated unemployed. In this report, the first suggestion which they have made is that the inferiority complex attached to manual work should be broken.

What attitude do you find among these young people of this country? They like to be Babus. No sooner they become graduates, they want to be the managers in the bank or some officers in the offices. But, they are reluctant to do manual work. In this connection, I would suggest that the craze for easy and quick money through speculation and unscrupulous means should be replaced by a liking for sincere, hard and productive work and while considering this, we have also to take into consideration suggestion which they have made that our students and the educated young people should give up their inhibition to progressive programmes and Government should assist them in the adoption of family planning. Yesterday we discussed this particular problem by way of calling attention notice and this also would help as and, of course, I am glad that the Government is taking steps on this particular question.

Coming to the main thrust of the particular resolution about educational remedies, I may mention a few of them. It is suggested and I would like to bring to the notice of the Hon. Minister, that the simple expansionist strategy should be replaced by a more radical and pragmatic educational policy, closely integrated with socio-economic needs. If you take into consideration the education policy and the system of education, you will find that it is not job-oriented and therefore, we find that many of the graduates coming out of the schools and colleges do not get any jobs.

I suggest that the curriculum and methodology of our educational system should be reconstructed particularly to cater to certain needs. First is the work experience, and social service should be introduced as an essential part of our education. It is at present lacking in our educational system. The reason why I say this is that after coming out of the colleges, our students do not get jobs. They are frustrated and the problem is aggravated. Work experience should take the form of diversified productive activi-

[Shri Bapusaheb Parulekar]

ties involving manual skill on farms, in workshops and factories. Therefore my suggestion for a change in the educational system.

Our educationists should recognise their responsibility in facilitating the tradition of our youth in engaging themselves in the academic world of work and life, which unfortunately is absent at present. They should be committed to the task of inculcating in our youth the necessary drive, vision and initiative, self-confidence and aptitude for self-employment. Unfortunately, this confidence is lacking in our youth. Though educated, they are not self-confident. There is need to introduce in our educational curriculum and methodology, some built-in element of flexibility so that these are continually adjusted to changed circumstances and our centres of advanced study should lay greater emphasis on applied research findings.

I would like to bring to the notice of the Hon. Minister two suggestions with reference to this educational system. The economic growth has to be accelerated at a faster rate in order to increase the economic capacity of our nation to absorb the educated man-power. Unless some steps are taken for the economic growth, there cannot be more jobs and unless we try to create more jobs, it would not be possible to solve the problem of unemployment.

I would like to bring to your notice the suggestion made by a Committee that the Government should vigorously accelerate the infra-structural development like expansion of rail and roads etc. in order to trigger of instantaneously the crash programme for employment expansion so that our engineers and other science graduates who are unemployed at present, would get jobs.

I would also suggest that there is considerable scope for the development of our natural resources like forests, water reserves, oil-fields, minerals, health, etc. Natural resources should be vigorously exploited which apart from promoting capital formation would widen the horizon of employment opportunities for our unemployed engineers and science graduates.

These are a few of the suggestions which I have tried to highlight, to put before this House, to bring to the notice of the hon. Minister. There are many other good suggestions which have been made in this Report. Apart from this Report of the Study Group there are other Committee Reports; they have also made suggestions. Therefore, what I say is that it is not necessary to appoint a fresh Youth Commission as has been suggested by the hon. Member. I have no objection if this Commission is appointed. But one more Commission would only mean that they will consider the previous Reports and they will make the same suggestions; some years will pass by and its Report, along with the other Reports, will go in to cold storage. We want action on this particular Report; we need some implementation of the suggestions made in this particular Report. In that connection, I would request the hon. Minister to tell the House what steps Government intend to take to implement the suggestions made in this particular Report...

श्री फूल चंद वर्मा: मेरा निवेदन यह है कि नये परिप्रेक्ष्य में एक आयोग का गठन किया जाय और छ: महीने में वह अपनी रिपोर्ट दे दे।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I have no objection. But I have my own doubts whether, in six months, we will get the report. Government will require six months to appoint the Commission itself. The problem will become more complicated. Therefore, in order that no more time is lost, this is my suggestion. if you want to appoint a Commission, you may appoint. But till the time you get the report, do not keep quit, try to implement the suggestions made in this particular Report.

Let us all come together and try to solve the problem of unemployment. With these words, I support the Resolution and I request the hon. Minister to consider the suggestions and try to implement them.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): The latter part of your suggestions will be taken into consideration.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, Similar to the Resolution which has been moved by my hon. friend, Shri Phool Chand Verma, some years ago—in the year 1959—I had moved one Resolution in this House.

There is no doubt that the problem of unemployment is very grave in this country, and Government is quite aware of this problem. Whatever suggestions and whatever plans are made by the Government are made with a view to seeing that the problem of unemployment is solved. But, now, it seems that we have to review the whole strategy of development which we have adopted and make new changes in that strategy so as to see that whatever investments we are making generate employment.

In this connection I would like to quote what Mahatma Gandhi had to say—because he thought of all these problems even before the independence of this country; he said:

> "Any plan, which exploits the raw materials of a country and neglects the potentially more powerful manpower is lopsided and can never tend to establish human equality."

Therefore, the Father of the Nation had thought how to manage, how to do the planning in this country, so that we not only use the raw material potentials of this country but also use the manpower potential in the country which is really the motive force for generating employment and growth in this country.

If you look to the answers which have been given to some of the questions, you will find that the number of Matriculates, as on 30-6-1980, who had registered themselves with the Employment Exchange is 39,70,541, the number of those educated upto Higher Secondary is 19,11,438, the number of graduates is 13,03,154 and the number of post-graduates is 1,11,837. These figures are, as I said, as on 30-6-1980, and the numbers may have gone up still further now.

If you look to the entire investment pattern of our planning, beginning from the First Plan to the Sixth Plan, you will find that we started with a modest investment of Rs. 2,000 crores in the First Plan.

Now we have jumped up to Rs. 97,000 crores of investment in the Sixth Plan. At least this is one of the biggest jumps that one can say, in our development effort which we began after our independence. This is the biggest investment which is really commendable so far as our achievements are concerned. If you look to the UN Development Decade, we have gone through the entire strategy of investment and the capital-output ratio so far as employment generation in the Third World is concerned it is a most significant observation:

> "The main objective of the UN First Development Decade was to ensure a minimum annual growth rate of 5 per cent of GNP of the developing country. Many countries have witnessed fairly respectable rates of growth in GNP in 1950 but the growth failed to make a dent on the problem of mass poverty and unemployment."

In 1975 the ILO report on the Work-Social situation has observed:

> "Compared with the hopes and aspirations, the efforts of development have been a failure, though not a complete failure. It was realised that all was not well with the development strategy in furthering

[Shri Chintamani Panigrahi]

the growth of GNP as a panacea for all ills. The real impact of the growth of GNP on the problems of poverty and unemployment has been quite dubious in the Third World countries. Increasing growth rate did not provide a guarantee against worsening unemployment or poverty in the developing country."

Therefore, Sir, you will find that the growth of GNP has nothing to do with the provision of employment or creation of more employment to the unemployed.

I would also like to draw the attention of the Minister. If you look to the great sacrifices of heroes like Bhagat Singh, Khudi Ram and others in those days, and those young people who participated in the liberation movement during the first four decades of our freedom struggle, right upto the 1942 Quit India Movement, they had some faith, they had some vision and they had leadership qualities in them and that was the inspiration that they gave to the countrymen and the countrymen could be inspired by their sacrifices. But to-day, after this post-Independence period, if you analyse what do we find? Is that leadership quality, is that vision, is that imagination, is that kind of sacrifice that we should build up this country anew, there in the new generation of the post-Independence period? That we have to very carefully look to.

Here some surveys were made in the Punjab University in the year 1980—some 6-7 months ago, as to what is their habit, how they look at the media, what is their way of thinking and all that. A very good survey was made by a very reliable Professor. What is the result of the survey?

"Student leaders listen more regularly to film music than news bulletins over the radio; while the number of those who see **TV feature** films is five times more than those who watch the Youth Forum programmes (which are meant to educate people) more of them look at Cinema advertisements in the newspapers than reading the editorial."

One of their habits is that they spend most of their time in gossiping or in other activities which never create employment or which never train them to be the best leaders of the next generation. That way we have to look at the entire thing.

You know from the beginning of 1968 to 1970 there was great campus unrest in almost all the Universities in USA. But the American authorities did not want to deal with the unrest in the campus by using police force or by using lathis or bullets. What did they do? They employed 3000 best psychiatrists..... (*Interruptions*) please learn something. When you were not born, I was there in the revolution. If you belong to Calcutta, your entire movement was started by us and not by you because you were not then born. What is your age?...

AN HON. MEMBER: Under-aged.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your date of birth?

He is an old leader of the Communist Party.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: At least unlearn what you have learnt. (*Interruptions*)

Sir, you will be surprised to know that they employed 3,000 best psychiatrists to go and talk to the students to know what they had in their minds and to find out why the student unrest was there. By two years of hard labour, the entire psychology and outlook of the students in the American University campus was changed and peace returned to the campus and they devoted themselves to the construction of new America. That was the new generation's thinking there.

Here I am only trying to submit before Government that we have so many programmes. For example we have a programme to train the educated youths so that they can get the jobs. What can the hon. Minister at the Centre alone do? I feel pity for the Central Government because they can only give money to the State Government. It is for the State Governments to take up the programmes. You will find for example there is a programme to train youths so that they can set up their own units or industries. Under the self-employed youth programme, the target fixed for 1979-80 was 1,00,229. This was the number to be trained for self-employment. They will set up their own units and create new employment in their own spheres. But, what happened to it? The target was 1,00,229; the number trained was only 39,899. Those who had undergone training were 28,527 and the number of trainees who had set up the units was 4,709. The programme was sanctioned by the Central Government. But, the Central Government never runs the training programme. It is the State Governments which run this. The number of trainees who have set up units is 4,789. But, the information in respect of the following states is:

Assam	Not reported.
Gujarat	Not reported.
Himachal Pradesh	Not reported.
Karnataka	Not reported.
Kerala	Not reported.
Orissa	Not reported.

grammes they may be or whatever be the planning efforts, the Central Government can only entrust them to the State Governments. But, unless they decide to take them up seriously, it is very difficult to solve the problem of unemployment in the country.

The backlog of unemployment from First Plan to this Plan has gone up to 15 million. It was only 3 million or so in the First Plan and it had gone up to five million in the next Plan. It went up to 15 million and odd now. This is the backlog. Whatever strategy we will have to evolve, we will also have to see the volume of investment that is going to be made. From Rs. 2,000 crores we are going up to Rs. 97,000 crores.

The capitalist countries wanted to see that Soviet Union perished. But what happened ultimately? In 1917, a group of young people of the Soviet Union wanted to build up their country by their own sacrifice. The band of young men with shovels in their hands were trying to build roads. They were asked by the great writer Mr. Maxim Gorky as to how could they do that in the snow clad Siberian region? The youths said that they could make the mountains bend their heads and they could see that one river goes and mixes up with another river. So, in their lifetime of sixty years, these youths have built up this new State.

Take the case of China. I had been to China in 1951. What we found there was that five million workers were digging up the canal. It involved Rs. 200 crores of investment. The target was to finish that within six months. But the youths said: 'No, we want to finish this ahead of this time.' That shows the determination and the sacrifives made by these youths. Unless the youth decide to build a new national we will not be able to achieve much merely through capital investment. The entire man-power, the great potential force and the teaming millions if they decide to add one man hour a day then what tremendous capital these 68 crore people will create.

Sir, time has come when we should not be-little our achievements of the past three decades and say that we have not achieved anything. Sir, we have built up an infrastructure which no other country in the world has done through democratic process. These are plus factors. There is the problem of unemployment and the

[Shri Chintamani Panigrahi]

young people are frustrated. We must provide them with ideology and leadership and they shall feel part and parcel of new India that we are building. I am quite sure in the new Sixth Plan in which we have given priority to employment some steps will be taken so that in the coming years, namely, 1982-83 and 1983-84 we can go to the people and tell them that millions of our people have found employment.

So, Sir, I support the spirit behind the Bill. We must try to do our best to see that the youth get employment but a commisison will not do anything. A commission can give employment to a few people and not to millions of our young people. So, I will appeal to the hon. Minister to see that all the programmes that we have undertaken to provide employment to the young people are implemented expditiously and with serious conviction.

श्री शिव कुमार ठाकुर (खंडवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री फूल चन्द वर्मा द्वारा जो रेजेल्यूशन प्रस्तुत किया गया है, मैं उन की भावना का स्वागत करता हूं, परन्तु जैसा कि अभी मेरे पूर्व-वक्ता ने भी कहा—इसका जो आपरेटिव-पार्ट है मैं उसका विरोध करता हूं। मेरा तात्पर्य यह है कि इस में जो कमीशन बैठाने की बात है उसका मैं विरोध करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 33 वर्ष बाद भी, कई पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान के बावजूद भी, आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक भयानक रूप लेती जा रही है। आज 42 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 62 रुपये प्रति माह खर्च नहीं कर सकते, इस का मतलब है कि 42 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन की प्रतिदिन की आय 2 रुपये भी नहीं है। आज हमारे देश में बेरोजगारी लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारी जो अर्थ-व्यवस्था है वह पहले से ही कुछ इस प्रकार की बनी है कि देश में पूंजी का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन इस से बेरोजगारी नहीं मिट रही है। आज हमारी अर्थ-व्यवस्था को रोजगारोन्मुख बनाने की सख्त आवश्यकता है। बेरोजगारी के कारण आज हमारे देश में मानव-शक्ति का बहुत ह्रास हो रहा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा इस से असन्तुष्ट हो कर निराशा के वातावरण में जी रहा है। यद इस पर शीघ्र नियन्त्रण नहीं किया गया, इस को शीघ्र नाहीं रोका गया, इस पर शीघ्र ध्यान नाहो दिया गयात तो हमारे देश की तरक्की के लिये हम चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितनी योजनायें बनायें, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आज हमारे देश में नेगेटिव-वोट की राजनीति चल रही है। इस का क्या कारण है? जिस प्रकार से रोटी को पलटने की आवश्यकता है उसी प्रकार से हमारे देश में भी लोगों में कुछ इस प्रकार की असन्तोष की भावना पैदा हो गई है कि वे किसी को पसन्द नहीं करते।

उसका कारण यह है कि आदमी की जो प्राथमिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, वे पूरी नहीं होती जिससे उसके मन में असन्तोष की ज्वाला भड़कती है। आज इस ज्वाला को शांत करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड-बैंक की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि हमारे देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। आज विश्व में चीन के बाद जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हमारा दूसरा नम्बर है। इससे हमारे देश के प्राकृतिक साधनों का दोहन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है इससे हमारे प्राकृतिक साधन, जैसे लोहा, कोयला भूमि आदि का दोहन बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते इसमें कमी नहीं लाई गई और प्लानिंग कर के जनसंख्या के अनुरूप बनाकर इनका उपयोग नहीं किया गया तो एक वह दिन आएगा जब हमारे प्राकृतिक साधन समाप्त हो जाएंगे, जिनसे हमें इन्कम होती है। फिर से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप में उपस्थित हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना कहना है कि आने वाले 20 वर्षों के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा-नीति बनानी पड़ेगी,

जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इसकी आवश्यकता प्रतिपादित की है। फूलचन्द वर्मा जी ने कहा है कि कमीशन बैठाया जाए, इससे कुछ नहीं होगा। कई कमीशन बैठाए जा चुके हैं, कई राजनीतिज्ञ, कई शिक्षा-शास्त्री और कई शिक्षक तथा समाज के प्रमुख लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने अपने विचार रखे हैं और उनकी रिपोर्ट्स ठन्डे बस्ते में पड़ी हैं। वे रिपोर्टें धूल खा रही हैं। आज उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है। हमें कोई चीज बाहर से नहीं लानी है। हमें देखना है कि एक इंजीनियर और एक डाक्टर को अपने शिक्षा काल में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या कमजोरियां उसमें रह जाती है* और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। पढ़ाने वालों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। जैसा कि शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली हमारे देश में चली आ रही है, इसमें हमें पूर्णतः परिवर्तन लाना होगा। आज नवयुवक क्यों आन्दोलन करता है, उसको पढ़ाने का वातावरण क्यों नहीं मिल पाता, उन कारणों को खोजने की आवश्यकता है, उन कारणों को हटाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश को मजबूत डाक्टर मिल सकें, मजबूत इंजीनियर मिल सकें, मजबूत ग्रेजूएट, पोस्ट ग्रेजूएट मिल सकें। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मैट्रिक, हायर-सेकेण्डरी ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे नव-युवक के सामने रोजगार की समस्या न रहे, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बिना किसी की सिफारिश के। उसे चप्पलें या जूते रोजगार कार्यालयों के चक्कर काटने में न फटने पड़ें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे उसके अन्दर एक आत्म-विश्वास पैदा हो सके और वह समस्याओं से लड़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना बनाई है। हम लोग जो दिल्ली में बैठ कर बेरोजगारी को दूर करने की योजनाएं बनाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। हमको इसके लिए गांव-गांव जाना होगा। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में बसती है, उससे सम्पर्क करना होगा। उनकी क्या-क्या तकलीफ है, कहां सड़कें नहीं हैं, कहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, कहां जमीन को कटने से बचाना है, किस प्रकार से किसानों की रक्षा करनी है, इन सब बातों को देखना होगा। जिन हाथों को काम नहीं है, उन हाथों को सही दिशा देनी होगी, सही उपयोग करना होगा। यह समस्या हमारे देश के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती। हमने देखा है जर्मनी में दो वर्ल्ड वार वहां पर हुए। जर्मनी ईस्ट और वैस्ट में बंटा हुआ है। ईस्ट जर्मनी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दो वर्ल्ड वार्ज ने उसको बड़ी भयानक स्थिति में डाल दिया था और उसको जर्जर कर दिया था। लेकिन इतना होने पर भी वहां की महिलाओं, बच्चों, नौजवानों ने अपने पैरों पर खड़े हो कर उस देश को फिर से आज इस काबिल बना दिया है कि वे पूरी दुनियां से टक्कर लेने की स्थिति में हैं। इंडस्ट्रीज, शिक्षा आदि जो वहां देखने को मिलती है और जिस प्रकार का वातावरण वहां देखने को मिलता है उसको देख कर जलन होती है। एक छोटा सा देश होते हुए भी वह बड़े देशों की तरह से फलफूल रहा है। वह बात हमारे देश में भी आ सकती है। जोश और वातावरण पैदा करने की बात है। आज जो शिक्षा दी जाती है वह ऐसी नहीं होनी चाहिये जो दूसरों की नकल हो। हड़तालें और तरह तरह के आन्दोलन करवाने की कोशिश यहां होती हैं और सहूलियतों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। हम लोग हों या विपक्ष के हों, किसी भी दल के हों, हम जो देश के पालक हैं हम देश के प्रति जवाबदार हैं। जनता ने हमों को यहां चुन कर भेजा है। हम ऐसी ठोस चीज बनाएं और लोगों को दें ताकि देश का भला हो, बेरोजगारी को खत्म करने में

[श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर]

मदद मिले। कुछ राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं जिन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होनी चाहिये। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिये। उन को हल करने के लिए हम सब को मिल कर एक समन्वित योजना बनानी चाहिये और देश के नौजवानों को देनी चाहिये ताकि वे आगे बढ़ सकें।

महाराष्ट्र में एक लाख व्यक्तियों को तीन सौ दिन तक साल में रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। वहां अस्सी प्रतिशत धन छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं, भू संरक्षण, जंगल लगाने पर खर्च करने की व्यावस्था की गई है। छोटे छोटे काम बड़ा महत्व रखते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए उनका अपना अलग विशेष महत्व होता है। आने वाले कल के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए उनका अपना ही महत्व होता है। राजस्थान में भी एक लाख साठ हजार व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है। उस में उन लोगों को पम्पिंग सैट, दुधारू पशु, भेड़ बकरी, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, सिलाई मशीनें, करघे आदि दिए गए हैं। जो निम्न वर्ग के गरीब लोग हैं उनके वास्ते इस तरह से कमाई के साधन जब पैदा कर दिए जाते हैं तो छोटी चीज होते हुए भी उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार से उनकी थोड़ी सी मदद कर दी गई है। इसी तरह से अगर लोगों को थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और जो समस्या बहुत बड़ी दिखती है वह सरल हो सकती है और वह बड़ी नहीं रह जाती है।

काम के बदले अनाज योजना भी मध्य प्रदेश में चल रही है। इससे भी बेरोजगारी दूर करने में मदद मिली है। यह एक साहसिक और बड़ा कदम साबित हो सकती है अगर इसका विस्तार किया जाए। अनाज के हमारे पास विपुल भंडार हैं। एक व्यक्ति को अगर हम तीन सौ दिन तक रोजगार इस योजना के अन्तर्गत दें तो एक साल में उसके लिए एक टन अनाज की आवश्यकता होती है। चालीस लाख टन अनाज अगर इस योजना में लगाया जाए तो इससे हमारे देश के दो करोड़ लोगों को साल भर पूरा रोजगार मिल सकता है। इससे तीन लाभ होंगे।

16.28 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

पहला यह है कि गरीबी के हाथ में पैसा जाएगा। दूसरे अनाज का मूल्य प्राप्त होगा। तीसरे गांव के लोगों को जो महंगा अनाज खरीदना पड़ता है वह नहीं खरीदना पड़ेगा। जिन किसानों को यह लाभ प्राप्त होगा उनकी बेरोजगारी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।

डेरी डिवलेपमेंट करपोरेशन की स्कीम मैंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखी है। वहां लगभग एक हजार गांव हैं। 950 गांवों में दूध की छोटी छोटी सहकारी समितियां बना करके वहां के गरीब, छोटे और आम किसान को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसी बात नहीं है कि वहां का किसान लोन नहीं लेता। लेता है। परन्तु उसमें कर्ज को पटाने की क्षमता है। गांवों में जब हम जाते हैं तो एक दो किसान हम को भी प्रार्थनापत्र देते हैं कि उनके कर्ज की किश्त करवा दी जाए। लेकिन खेड़ा, शोलापुर, कोल्हापुर, इंच्छल करंजी, अखलूज में आम किसान, छोटा आदमी, नौजवान अपने पैरों पर पावर लूम के माध्यम से, शुगर इन्डस्ट्रीज के माध्यम से, पोलटरी फार्म के माध्याम से, खड़ा हो रहा है। इसी तरह की चीज में इस समस्या का हल निहित है। शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। समाज के सभी लोगों को, प्रगतिशील किसान मजदूर संगठनों को, शासक पक्ष तथा विरोधी पक्ष के नेताओं को मिल कर इस पर काम करना चाहिये। ऐसा किया गया तो इसका अच्छा फल हम लोगों को मिल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उनकी भावना से मैं सहमत हूं।

*SHRI C. PALANIAPPAN (Salem): Mr. Chairman, on behalf of my party, the D.M.K., I would like to make a few suggestions in support of my hon. friend, Shri Phoolchand Verma's Resolution demanding the constitution of a National Youth Commission to solve

*The original speech was delivered in Tamil.

the growing unemployment problem in our country.

The organised industrial sector in our country has created 21 per cent job opportunities, the State Governments, the Central Government and the public sector undertakings of both the State and the Central Governments 23 per cent job opportunities and the agricultural sector 46 per cent job opportunities. The unemployment problem has become a national problem and it cannot be tackled by the normal ways of budgeting. The national budget should be such as to create job opportunities through massive investments both in industries and in agriculture. Then only we will be able to touch the fringe of the problem of unemnloyment of about 4 crores of educated youths in our country.

In Tamil Nadu, 10.8 lakhs are registered in the Employment Exchanges. In Salem alone about 66000 youngsters have registered in the Employment Exchanges. During Dr. Kalaignar Karunandhis regime the registrants in the Employment Exchanges were only 2.5 lakhs. According to the authoritative statistics, the unemployment in the State of Tamil Nadu is 16.1 per cent as against 8.5 per cent for the country. This is the highest among all the States in the country. The unemployment in Tamil Nadu has grown beyond control during the ADMK regione. The number of rural people below the poverty line in the State is 63 per cent as against 52.52 per cent in 1976. It was 45 per cent only during the rule of my leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. The State of Tamil Nadu should receive special attention in the hands of Central Government.

While we have to plan on a massive scale we should bear in mind that the drift from rural to urban areas should be arrested. The rural areas should not only be made self-sufficient but also self-reliant. In other words, the job opportunities should be created only in rural areas. In 1980-81 Rs. 144.79 crores was allotted for rural development. It was like dropping asafoetida in the sea. We should formulate schemes through the Khadi and Village Industries Commission. The rural areas should have tiny industries. The District Industries Centres should also be given the due role in the creation of small industrial units in the rural areas. We should have tiny units for manufacturing soaps, matches, handmade papers and boards, mats, etc. We should have cooperative handloom units as also cooperative powerloom units. Small oil crushers to have coconut oil, groundnut oil, castor oil and other edible oils should be set up. We should plan for setting up small units for manufacturing aluminium vessels for small agricultural implements for bricks and tiles. Ancillary units for producing small items required by large units should also be set up. We can encourage carpentry in rural areas. Printing and Binding units can also be thought of. The Government should arrange for the supply of raw materials and also for procuring the products The intermediaries should be abolished. Power supply to rural industries should be given precedence. These tiny and small units will generate employment opportunities for the unemployed as also for the agricultu ral labour who do not have employment throughout the year. You know, Sir, that agricultural itself is seasonal and naturally, during the lean reasons, these units will enable them to supplemement their income. The objective should be to create employment opportunities for every 100 unemployed in the rural area through setting up either a tiny unit or a small unit.

We will be failing in our duty if we do not produce more to meet the basic minimum requirements of essential commodities by the common people throughout the length and breadth of the country. We should also ensure that there is a nationwide distribution network for the essential commodities. Even in this sector we will be able to create job opportunities for the educated unemployed. The right of employment must be enshrined in our Constitution. We cannot allow to

[Shri C. Palaniappan]

waste the manpower available within the country. We should also formulate schemes for helping the disabled and the old people in our country.

The wise leaders of our country will no doubt formulate meaningful schemes not only for containing the problem of unemployment but also for eliminating the courage of unemployment from the country.

Before I conclude, I would say that this National Youth Commission should become the potent instrument and endeavour earnestly in the direction I have suggested.

With these words I resume my seat.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर): सभापति महोदय, श्री फूलचन्द्र वर्मा ने जो प्रस्ताव रखा है और अपने विचार प्रस्तुत किया है, उनका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इस संबंध में हमने जो योजनाएं बनाई, उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम अपनी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करें। हमें विश्लेषण और चिन्तन करना होगा कि हम इसमें कितने सफल हुए?

प्रश्न यह उठता है कि न तो जनसंख्या की वृद्धि को हम रोक पाये और न बेरोजगारों की बढ़ती हुई पलटन के संबंध में हम कोई यथोचित कदम उठा सके? इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

कोई भी देश जब तक उस के नागरिक परिश्रमी, चारित्रवान और दृढ़निश्चयी न हों, वह उन्नति नहीं कर सकता। कितनी भी योजनाएं बना दीजिये, परन्तु ये गुण राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति या नागरिक में होने आवश्यक हैं।

शिक्षा जो हमारी आधारभूत संरचना का स्वरूप पैदा करती है, उसके बारे में हमने अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं बनाई, जिससे कि हम देश को उन्नतिशील बना सके। न हमने नैतिक दृष्टि से उत्थान किया है और न हमने रोजगार की दृष्टि से उत्थान किया है। दोनों दृष्टियों से हमारा पतन हो रहा है, यह हमारे लिये सोचने की बात है।

मेरा तो यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में लोक-सभा में 3 दिन तक बराबर डिस्कशन होना चाहिये और उस पर हमें अपने व्यूज एक्सप्रेस करने चाहियें। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में, चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेंस और एजूकेशन मिनिस्टर्स कांफरेंस में इसके ऊपर विचार होना चाहिये क्योंकि जब तक हम इस शिक्षा नीति के बारे में पूर्ण तौर पर एक निश्चय नहीं करते। हमने नीति बनाई है 10+2+3, की, इस नीति के ऊपर भी कुछ स्टेट्स ने अमल किया है, उस का पालन किया है और कुछ ने उस का पालन नहीं किया है। जब हम ने यह पालिसी बना दी है 10+2+3 की तो हमें इस को इम्पलीमेंट करने का प्रयास करना चाहिये। हम ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम रखा था उस में भी हम ने इस की व्यवस्था की थी अप्रेंटिशिप की और मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर सेट अप करने चाहियें जो कि आठवीं पास करने वाले और दसवीं फेल लड़कों को भी एक या डेढ़ साल की ट्रेनिंग दे कर इस योग्य बना दें कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

55 वर्ष की आयु का जो सुझाव है उस को हमारी राजस्थान सरकार ने मान्यता दी है और हम लगातार सात वर्षों से इस सुझाव को कार्यान्वित कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को भी और जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उन को भी 55 वर्ष की आयु रिटायरमेंट के लिए मान कर काम करना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी कदम उठाना चाहिए।

ओवर टाइम की बात भी इसी तरह से आप देखें, मैं ने प्रश्न पूछा तो उस के जो कैलकुलेशंस लगाए गए हैं उन के हिसाब से हमें बताया गया कि 1 हजार करोड़ रुपये ओवरटाइम में दिए जाते हैं। आप यह समझिए कि इस 1 हजार करोड़ रुपये से कितने व्यक्तियों को एम्पलायमेंट दिया जा सकता है।

मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो वहां लोग पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं जब कि पढ़ने लिखने के बाद उन्हें

सर्विस तो मिलती नहीं और हमारे लड़के जो खेतों में काम करते थे, उस के लायक भी नहीं रह जाते। तो हम क्यों पढ़ाई की तरफ बढ़ें? यह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी जो शिक्षा है उसे हमें जाब-ओरिएंटेड, एम्पलायमेंट-ओरिएंटेड करना पड़ेगा और यह प्रयास करना पड़ेगा कि शिक्षा के अन्दर जो सेकेंड्री या हायर सेकेंड्री से आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों का सेलेक्शन योग्यता के आधार पर कर के, जो योग्य हों उन्हीं को बी. ए. और एम. ए. के लिए आगे शिक्षा दी जाय।

आज विशेषकर जो डाक्टर और इंजीनियर हम तैयार कर रहे हैं वह भी अनएम्पलायड हैं, यह भी हमारे लिए सोचने की बात है क्यों कि लाखों रुपये खर्च करते हैं डाक्टर्स और इंजीनियर्स को तैयार करने पर लेकिन उन को भी एम्पलायमेंट नहीं मिलता है।

इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र में जो शिक्षा की प्रणाली है उस में आमूलचूल परिवर्तन कर के हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): सभापति महोदय, देश में पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोगों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस के प्रति और उस का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उस के प्रति हमें बड़ी गंभीरता से सोचना है। इस बेरोजगारी का प्रभाव केवल हमारे अर्थतंत्र पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि देश के भविष्य पर जो पड़ेगा.. **(व्यवधान)**.... प्रजातंत्र की बात में क्या कहूं, इस देश में कौन सी स्थिति आ सकती है अगर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर पाये, उस से हमें सावधान रहना चाहिये।

जहां तक पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी की बात है, उसके लिए जहां हमें बड़ी जल्दी कारगर ढंग से शिक्षा में परिवर्तन करना है, वहां कुछ ऐसे टेम्पोरेरी तरीके अपनाने हैं, जिनके द्वारा हम कुछ लोगों को एम्पलायमेंट दे सकें।

आज एक तरफ हम लोगों को पूरे समय का रोजगार देते हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारों की टोली बढ़ती चली जा रही है। क्यों न हम मौजूदा एम्पलायमेंट का बंटवारा कर लें? अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि ओवरटाइम का बहुत पैसा दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि काम के घंटे घटा कर उस अनुपात में और लोगों को भर्ती किया जाबे। काम के घंटे घटाने से बहुत से नये लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और आंशिक सुविधा मिलेगी।

जहां तक रिटायरमेंट का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से 55 वर्ष पर कर्मचारियों को रिटायर कर देना चाहिए, ताकि बेरोजगारों की सेना को मौका मिले। आज बेरोजगारी की हालत यह है कि पढ़े-लिखे नवयुवक मेडिकल कालेजों और हास्पिटलों में अपना खून बेचने के लिए मजबूर हैं। बेकारी से तंग आ कर वे आत्महत्या कर रहे हैं, नदियों में डूब रहे हैं, रेलों से कट रहे हैं, जहर खा रहे हैं। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने का प्रश्न है।

यह भी आवश्यक है कि एक व्यक्ति के पास एक ही धंधा, एक ही काम रहे। एक व्यक्ति सम्पत्ति पर भी कब्जा किये हुए है, वह खेती भी करता है, नौकरी भी करता है और उसके परिवार के लोग इंडस्ट्री भी चलाते हैं।

पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज कायम होनी चाहिए, जिन का स्वामित्व, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट उन्हीं लोगों के पास हो और वही उन्हें चलायें।

आज हमारे देश में टेम्पोरेरी और एड हाक बेसिस पर एपायंटमेंट होते हैं। यह बेरोजगारों का शोषण है, उनके साथ भ्रष्टाचार है। एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए रखा जाता है—पैसा ले कर रखा जाता है और छः सात महीने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद वह बेचारा फिर पैसा इकट्ठा कर के दूसरी जगह ढूंढता है। टेम्पोरेरी एपायंटमेंट्स

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

और एड हाक बेसिस पर होने वाली नियुक्तियों से लोगों को नुकसान होता है, इस लिए उन्हें समाप्त किया जाये। लोगों को पर्मानेंट जाब दिया जाये और जो काम न कर सके, उसको रिवर्ट कर दिया जाये।

शिक्षा के तरीके को इस तरह बदल दिया जाये कि लोगों को रोजगार मिल सके।

प्रो. सत्यदेव सिंह (छपरा): सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर): क्यों करते हैं?

प्रो. सत्यदेव सिंह: मैं इस लिए विरोध करता हूं कि जनसंघ का नारा था—उसने लेबल बदल कर अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रख लिया है—कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम।

श्री फूल चन्द वर्मा: वह अभी भी है।

प्रो. सत्यदेव सिंह: लेकिन जब इन लोगों को मौका मिला, जब वे शासन में आए, तो वे इस बात को भूल गए और राष्ट्रीय हित को ताक पर रख कर आपसी झगड़ों में उलझ गए, वे इस बात पर झगड़ा करने लगे कि प्रधान मंत्री कौन बने, जिससे देश का भला नहीं हो सका। यह तो उनका प्रस्ताव मात्र है; वस्तुत: वे कुछ नहीं करना चाहते हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप ने कहा है कि काम के घंटे कम कर के दूसरे लोगों को मौका देना चाहिये। दूसरों को मौका तो मिलना चाहिए लेकिन जब तक कर्मचारी काम के घंटों के अनुसार निष्ठापूर्वक काम नहीं करते हैं, तब तक देश का भला नहीं हो सकेगा, देश का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। काम के घंटे कम करना राष्ट्र-हित के अनुकूल नहीं है।

माननीय सदस्य ने अवकाश-ग्रहण की आयु को कम करने का सुझाव दिया है। मैं इसको सही नहीं मानता हूं। काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद अचानक 55 वर्ष के बाद आप उसको हटा दें, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जो शिक्षा दी जाती है, उसमें शारीरिक श्रम का स्थान नहीं है। हमारे बच्चे विद्यालयों और महाविद्यालयों, स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें शारीरिक श्रम का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, इस प्रकार वे निकम्मे हो जाते हैं और उनको केवल नौकरी पर ही आश्रित रहना पड़ता है। जहां पर देश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है, वहां के नवयुवकों को विद्यालयों में शारीरिक श्रम करने की क्षमता न हो सके, तो उससे देश सुन्दर नहीं रह सकेगा। इसलिए जहां एक तरफ लड़कों को स्कूलों और कालेजों में किताबी शिक्षा दी जाती है, दूसरी तरफ उन्हें यह भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिससे वह शारीरिक श्रम करने योग्य बन सकें। योग्य बनकर अपने देश के, अपने राष्ट्र के अभ्युदय विकास के लिए कारगर योगदान दे सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): I share the deep concern of the hon. Member, Shri Phool Chand Verma for the educated unemployment prevailing in the country, which has prompted him to move this Resolution.

I have also heard the speeches made by hon. Members, Shri Mool Chand Daga, and Shri Mukunda Mandal while moving their amendments on the resolution. I have noted the suggestions made by Shri Vyasji, Shri Sultanpuri, Shri Mollah, Shri Namgyal, Shri Nawal Kishore Sharma, yourself and Shri Parulekar, and then Shri Palaniappan, Shri Vridhi Chand Jain, Shri Satya Deo Singh, and others. I am very very grateful to the hon. Members for the suggestions they have made.

As regards their suggestions concerning reforming the educational system those will be sent to the concerned Ministry. I do not think that the educational system alone should be blamed for the alleged failure of the planning process in channelising the youth into productive avenues, as has been made out in the Resolution before the House, because the existing unemployment situation is also the result of a large number of other factors. Important among these are the rapid population growth and the inadequate pace of development over the years. The educational and training system has no doubut, an important role to play in oreparing the youth for various developmental activities as has been emphasised by every member who has spoken on the Resolution. Government have recognised this fact and have therefore been taking a number of steps over the years for making the education system responsive to the needs of development.

I would like to refer to some of these steps here. A vast network of ITIs and an Apprenticeship Training Programme have been developed to train craftsmen and technicians for the industries. Entrepreneurship training programmes and the recent TRYSEM programme train educated youth in urban and rural areas for self-employment. Over and above these, a number of youth programmes like the scheme for Nehru Yuwak Kendras, the National Service Scheme etc., involve student and non-student youth in community and development activities. The process of re-orienting the education and training system to employment and making it relevant to life, is being continued in a more vigorous manner in the Sixth Plan. I would like to mention some of the important programmes included in the Plan for this purpose. Programmes for introducing work experience and for increasing the practical bias in secondary schools would be strengthened and vocationalisation of secondary education will be based on detailed surveys of work opportunities. The Industrial Training Institutes would be revamped to make their training programme self-employment and production oriented. Post-graduate education and research would concentrate on areas relevant to national development objectives. Institutions of higher learning would be encouraged to involve themselves in development activities in the community.

The Sixth Plan also envosages concerted efforts to forge beneficial links among education, employment and economic development. The House would be glad to know that a Committee of Experts has already been set up by the Planning Commission to examine several aspects of the issues involved in detail. This Committee has already made a number of suggestions and is currently preparing guidelines for formulating specific programmes for the purpose. Steps will be taken during the Sixth Plan to implement these programmes.

The Sixth Plan also envisages the formulation of a National Youth Policy incorporating a strategy for involving youth in national development. I may and that a National Youth Board is already functioning under the chairmanship of the Minister for Education for advising the Government on youth programmes and policies. This Committee includes officials as well as non-officials, Members of Parliament and representatives of student unions etc. The Board is the highest apex booy in the field of youth development.

The Resolution moved by the hon. Member states that there is a lack of direction in providing employment to the educated youth during the Sixth Plan. This is not correct since the Sixth Plan includes a large number of programmes which would generate substantial employment opportunities for the educated. The Plan proposes a new deal for the self-employed through a package of measures consisting of training, credit, marketing and general guidance to the public regarding facilities available. An important feature of the Sixth Plan is

[Shrimati Ram Dulari Sinha]

the decentralised strategy, for manpower planning and employment generation, proposed to be adopted. The District Manpower Planning and Employment Generation Councils proposed for all the districts would prepare employment strategies and plans relevant to each district and monitor their implementation.

Reference to questions like payment of unemployment allowance, reforming of the employment exchanges, etc. were made by hon. Members who spoke on the Resolution. Government's stand on the question of paying unemployment allowance to the unemployed has been clarified a number of times in this House and in the other House also. Government are not in favour of paying unemployment allowance in view of the large financial implications of the proposal. Government would rather utilise such resources for creating productive employment opportunities for the unemployed rather than use them for paying cash doles.

As for the emloyment exchanges, the recommendations of a Committee which recently examined the working of the employment exchanges are already receiving consideration of the Government. The Sixth Plan also envisages the restructing of the employment exchanges in such a way that they may render a more effective service in guiding and assisting those seeking opportunities for self-employment.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I wanted to know whether the Government is interesting in giving unemployment allowance to the youth.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: To sum up, therefore, Government are already taking steps to reorient education and training to make it relevant to a gainful working life. The Sixth Plan has devoted a good deal of attention to employment generation, contrary to what the Resolution before the House states. An Expert Committee is already going into the linkages between education, employment and development and a National Youth Board also already exist for advising Government on youth development. In the circumstances, therefore, there is hardly any need to set up a National Youth Commission as proposed in the Resolution. I would, therefore, request the hon. Member to withdraw the Resolution.

Mr. Chairman, Sir, when you made a speech on this Resolution you said lot of things. It reminded me of the days when we were also working among youth, particularly among rural youth.

आपने, सभापति जी, थोड़ी देर पहले अपने भाषण में कहा था कि आप सैक्रेटरी थे, यूथ आन्दोलन के नेता थे

आप ने सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल की याद दिलाई। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन वह एक जमाना था--

चमकता है शहीदों का लहू,
    कुदरत के पर्दे पर।
शफक का हुस्न क्या है,
    शोखिये-रंगे हिना क्या है?
गुनहगारों में हूं शामिल,
गुनाहों से नहीं वाकिफ।
सजा को जानती हूं मैं,
    खुदा जाने खता क्या है।
नया बिस्मिल हूं मैं वाकिफ नहीं,
    रस्मों शहादत से।
बता दे तू हि अे कातिल
    तड़पने की अदा क्या है।
उन्हें यह फिक्र है हरदम,
    नयी तर्जे जफा क्या है?
हमें भी शक है देखें
    सितम की इन्तिहा क्या है।"

आज हम निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं। वो जमाना था शहादत का, उस समय मजा आता था, आज हम लेने-देने की बात करते हैं। आज देश के नौजवानों को अनुशासन में बांधने के लिए सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री फूल चन्द वर्मा: माननीय सभापति महोदय, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के संबंध में जो मेरा प्रस्ताव था, उस समस्या को हल करने के लिए इस सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने भाग लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। माननीय मंत्री महोदया ने भी जानकारी दी कि इस बारे में सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है, लेकिन कुछ बातों का अपने भाषण के दौरान उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए थे, उनकी ओर या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या वे सफाई के साथ टाल गईं। जैसा कि मैंने सुझाव दिया था कि काम के अधिकार को हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार रोजगार कार्यालयों की बात उन्होंने की, मेरा इस बारे में सुझाव था कि रोजगार कार्यालयों के द्वारा सरकार को जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, वे सही नहीं नहीं होते, क्योंकि रोजगार कार्यालय शहरों में हैं। गांवों के अंदर जो बेरोजगार हैं, किसानों के जो बेटे पढ़-लिख जाते हैं, वे अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाते। इसलिए मेरा सुझाव था कि रोजगार कार्यालय ब्लाक-लेवल पर होने चाहिएं, ताकि गांव के लोग अपना नाम वहां पर दर्ज करा सकें। इससे सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि उसे सही आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे, इस संबंध में मंत्री महोदया ने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार विदेशों में रोजगार कार्यालय स्थापित करने के बारे में भी मैंने निवेदन किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे साउथ में केरल, कर्नाटक, मद्रास . . .।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: उसमें सुधार लाने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी की बात कही है।

श्री फूल चन्द वर्मा: मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने पहले भी इस बारे में बहुत सी कमेटियां बनाई हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों का क्या हुआ है। मुझे याद है कि आज तक इस प्रकार की 5-7 कमेटियां बनी हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट्स आपने कोल्ड स्टोरेज में रखवा दी हैं। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि उन रिपोर्ट्स पर कोई एक्शन लिया गया हो। आज इस बेरोजगारी की समस्या से प्रजातंत्र को खतरा है। अगर इसका समय रहते समाधान नहीं किया गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए, लेकिन सामने के जो सदस्य बैठे हैं वे इस गंभीर समस्या पर भी अपने दल के ऊपर उठकर नहीं बोले। इसका मुझे दुख है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर आर एस एस को जबर्दस्ती घसीटने की कोशिश की है। मैं पूछना चाहता हूं कि मोरवी में जब बाढ़ आई थी तो कांग्रेस के हमारे बंधु कहां थे ?

एक माननीय सदस्य: श्रीमती इंदिरा गांधी गई थीं।

श्री फूल चन्द वर्मा: कब गई थीं मुझे मालूम है। सड़ रही लाशों को किन्हों ने उठा कर उनका अंतिम संस्कार किया था, उनकी सेवा की थी? आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि हर जगह पर चाहे हैदराबाद का मामला हो या और जगह का है, आर एस एस को बीच में घसीटने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। खुद कांच के मकानों पर बैठ कर दूसरों पर पत्थर फेंकना अच्छी बात नहीं है। इस तरह की हिम्मत आपको नहीं करनी चाहिये। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिये।

जिस ढंग से उत्तर दिया गया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। नवयुवक आज किमकर्तव्यविमूढ़ हैं। सड़कों पर वे घूम रहे हैं। निराश हो कर वे असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर असामाजिक तत्वों के साथ मिल कर काम करता है तो

[श्री फूल चन्द वर्मा]

वह प्लानिंग के साथ काम करता है । उस का उस ओर दिमाग ज्यादा लगता है। इस वास्ते मैंने प्रार्थना की है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा । ओवर टाइम का एक हजार करोड़ रुपया दिया जाता है । इसको रोका जाए। यह एक अच्छा सुझाव है। इसकी मैं तहेदिल से सराहना करता हूं । 58 से घटा कर 55 वर्ष की अवकाश लेने की आयु के बारे में जो सुझाव दिया गया है इसके मैं पक्ष में नहीं हूं और इसलिए नहीं हूं कि आज किसी परिवार में अगर एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और वह अपने परिवार की गाड़ी को खींच रहा है और उसका कोई लड़का मैट्रिक में, कोई इंजीनियरिंग या डाक्टरी के आखिरी साल में पढ़ रहा है तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को अगर रिटायर कर दिया जाए तो उसके बच्चों की शिक्षा बीच में ही रुक जाएगी । इस तरह से बेरोजगारों को हम रोजगार तो ज्यादा नहीं दे सकेंगे लेकिन बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ने लग जाएगी ।इस सुझाव को अगर मान लिया गया तो अस्सी हजार को रोजगार दे कर लाखों को बेरोजगार करके हम उनको सड़कों पर ला कर खड़ा कर देंगे । मैं बापू साहेब पारुलेकर का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने यह जो सुझाव रखा है जब मैं इसको परिपेक्षय में देखता हूं तो मजबूर हो कर मुझ को इसको अस्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ता है ।

कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है कि बीस सूत्री कार्य क्रम के आधार पर देश के शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है । यह कार्यक्रम किस का है? अगर यह सरकारी है और पार्टी का नहीं है तो इस में विरोधियों को क्यों नहीं लिया गया है? मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कमेटियां बना कर उन में केवल कांग्रेसियों को लिया गया है, किसी विरोधी को नहीं लिया गया है, संसद सदस्य, एम एल ए, जन पद अध्यक्ष और पंच आदि जो विरोधी दलों के हैं उन तक को नहीं लिया गया है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या कमेटियों में केवल लेने से काम चल सकता है? देश के विकास में सहयोग करें।

श्री फूल चन्द वर्मा: समितियों का निर्माण क्यों करते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी की यह कमेटी है और यह कार्यक्रम है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जब खर्चा इस कमेटी का सरकार बरदाश्त करती है तो उस में विरोधियों को भी रखना चाहिये। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है और इस कारण और भी समस्यायें खड़ी हो रही हैं।

आपने हल्के ढंग से घुमा फिरा कर, गोल-माल तरीके से उत्तर देने की कोशिश की है । मैं चाहता हूं कि विषय की नजाकत को आप पहचानें । समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है । जिस प्रकार गुजरात में आन्दोलन चल रहे हैं, असम में चल रहे हैं, उनकी तह में आप जाएं । इनके पीछे यही एक समस्या है, यही भावना निहित है । पूरे देश में यह आग फैल रही है । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस समस्या को सरकार गम्भीरतापूर्वक ले । मेरे प्रस्ताव से आप सहमत नहीं इसका मुझे दुख नहीं है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस समस्या को आप हल करें ।

छठी योजना में इस समस्या को हल करने के लिए आपने एक कमेटी बनाई थी । वह कमेटी क्या करेगी, किन बिन्दुओं पर विचार करेगी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । उस के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है, यह भी बताने में आप समर्थ नहीं हैं ।

मैं सोचता हूं कमेटी 5 साल तक काम करेगी और जब दूसरी सरकार आयेगी तो उसकी रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में बन्द हो जायगी । इस प्रकार से इस समस्या को सुलझाने का तरीका ठीक नहीं है, इससे बेकारी की समस्या सुलझेगी नहीं ।

आपने अभी कहा हम बेकारी का भत्ता नहीं देना चाहते । शायद आपको पता न हो कि संसार के 34 देशों में वहां के बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी का भत्ता दिया

जाता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 41 देश ऐसे हैं जो बेरोजगारी का भत्ता दे रहे हैं। और उसके पीछे एक ही भावना है कि युवा शक्ति का जो राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान होना चाहिए उससे वह विमुख न हो सके। ....

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : हमारे यहां भी 8 राज्यों में दिया जा रहा है, और जिसका जिक्र मैंने कई बार इसी सदन में किया। बार-बार उसी बात को दोहराना अच्छा भी नहीं लगता।

श्री फूल चन्द वर्मा : आपने जिक्र किया होगा। मध्य प्रदेश के अन्दर पटवा सरकार ने शपथ लेते ही इस बात की व्यवस्था की कि मध्य प्रदेश के अन्दर रहने वाले प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे।

एक माननीय सदस्य : 1977 के इलेक्शन मैनीफेस्टो में तुम्हारे मैनीफेस्टो में लिखा था।

श्री फूल चन्द वर्मा : आप सुनिये। सभापति महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को जिस भावना से रखा था उसके पीछे कोई दलीय भावना मेरी नहीं थी। मैंने इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया था और दो ही पक्षों के सदस्यों ने इसको गम्भीरतापूर्वक लिया है। लेकिन जहां तक मंत्री महोदय का सवाल है उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, सरकार की नीति बताई है, मैं सोचता हूं वह अपर्याप्त है। और मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो मेरा प्रस्ताव है उसे राजनीति के प्रतिपक्ष में न देखते हुए, बल्कि जो यह गम्भीर समस्या है जिससे हमारा आर्थिक तंत्र तहस नहस हो गया है, हमारी योजनाएं फेल हो रही हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो लोग बेरोजगारी की पंक्ति में खड़े हो गये हैं, उसको खत्म करने के लिए लोगों को रोजगार देने के लिये आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो प्रस्ताव है इसको दलीय स्थिति से ऊपर ले कर, पूरे सदन को विश्वास में ले कर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो देश के अन्दर जो करोड़ों नौजवान चप्पल फटकाते घूम रहे हैं उनको राहत मिलेगी और इस देश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये एक नया रास्ता हमें दिखाई देगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: There are two amendments. No. 1 is by Shri Mool Chand Dagga and No. 4 is by Shri Mukunda Mandal.

Shri Mool Chand Daga is not present.

I put amendment No 1 moved by Shri Mool Chand Daga to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Mukunda Mandal, are you withdrawing your amendment No. 4?

SHRI MUKUNDA MANDAL: No, I am not withdrawing.

MR. CHAIRMAN: I shall put amendment No. 4 moved by Shri Mukunda Mandal to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, I put the Resolution moved by Shri Phool Chand Verma to the vote of the House.

The question is:

"In view of the fact that the present educational system does not equip and prepare the youth for meeting the challenges of life, the whole planning process has failed to channelise our youth power into productive channels, and there is lack of direction in providing employment to the educated youth during the Sixth Plan period; this House urges upon the Government to constitute a National Youth Commission immediately to examine and suggest,

[Mr. Chairman.]

within a period of six months, appropriate measures for solving the problem of unemployment amongst the educated youth."

The Motion was negatived.

17.16 hrs.

RESOLUTION RE: DEVELOPMENT OF HILLY REGIONS

MR. CHAIRMAN: We now take up the next Resolution. Prof. Narain Chand Parashar.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"This House urges upon the Government to set up a Parliamentary Committee to look into the extremely slow pace of industrial development and lack of adequate infrastructure, like, railway lines, roads, waterways, air-ways, bridges and other amenities like postal services, telecommunications, drinking water, banking and health services, institutions for technical and vocational education and the promotion of tourism, hydel-generation, forestry, agriculture including horticulture, irrigation, mass communication system in the hilly regions of the country, resulting in their extreme backwardness and to suggest ways and means to ensure their rapid economic development so as to bring them at par with the developed regions of the country within a period of five years."

माननीय सभापति जी, इस प्रस्ताव के द्वारा मैं भारतवर्ष के सभी पर्वतीय प्रान्तों, पर्वतीय क्षेत्रों, पिछड़े और गिरिजनों से भरे हुए क्षेत्रों की पीड़ा इस सदन के सामने पेश कर रहा हूं।

हमारे देश में विकास का कार्यक्रम चला, प्रगती के चरण आगे बढ़े और आजादी से भी पहले 1938 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रेरणा से श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना समिति बनी जिस में कहा गया था कि सारे देश के विकास के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रतिज्ञा करती है और उसके लिये एक योजना बनाती है।

जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश के कर्णधार, भारत के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने प्लानिंग को देश का एक इम्पार्टेन्ट आस्पेक्ट समझकर पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला जारी किया। पहली दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं बनी और योजना आयोग का गठन हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसके द्वारा देश के आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करने का जो प्रयास हुआ, उससे भारत के कोने-कोने में एक नई आशा और नये साहस का संचार हुआ।

मुझे उन दिनों की याद आती है जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। उस समय की बात है ग्राम-ग्राम में एक नई आशा का संचार और स्फूर्ति देखने में आया लोगों ने समझा कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। बहुत से कार्यक्रम चले और शुरू हो गये। उस समय एक गलती हमसे हो गई कि सारे भारतवर्ष के लिये एक यूनिफार्म पैटर्न आफ प्लानिंग चुन लिया गया, एक सामान्य आयोजना का आधार, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक विषमताओं को नहीं देखा गया। नताजा क्या हुआ? हरेक सैक्टर, विभाग और कार्य के लिये धनराशि मुकर्रर की जाने लगी।

मैं मूल समस्या की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिला रहा हूं। रेलवे लाइन बननी है, पोस्ट आफिस खुलना है या कोई हवाई अड्डा बनना है या बिजली का प्रोजेक्ट बनना है, राष्ट्रीय मार्ग बनना है या कोई इंडस्ट्री लगनी है या कोई पुल बनना है, सारे देश के लिये एक अनुरूप पैटन चुन लिया गया। नतीजा यह हुआ कि प्रगति के इस मैदान में जहां पहले ही बहुलता थी, जहां पहले ही प्रगति थी, वहां तो प्रगति